

ग्रामीण विकास में वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता

(वित्तीय साक्षरता से ग्रामीण जीवन में सामाजिक और आर्थिक विकास का राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के विशेष संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

The Need of Financial Literacy in Rural Development

(A Sociological Studies of Social and Economics Development in Rural Life by Financial Literacy in Special Reference to Hanumangarh District of Rajasthan)

Paper Submission: 02/03/2021, Date of Acceptance: 24/03/2021, Date of Publication: 25/03/2021



क्रान्ति बंसल
शोधार्थी,
समाजशास्त्र विभाग,
टांटिया विश्वविद्यालय,
श्रीगंगानगर, राजस्थान, भारत



सतीश कुमार
सह प्राध्यापक,
समाजशास्त्र विभाग,
टांटिया विश्वविद्यालय,
श्रीगंगानगर, राजस्थान भारत

सारांश

वर्तमान समय में नाबार्ड द्वारा वित्तीय साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। वित्तीय साक्षरता की शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता तथा साक्षर लोगों में वित्तीय जागरूकता का अभाव पाये जाने के कारण वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता अधिक है। इस महत्वपूर्ण कार्य को नाबार्ड द्वारा सहकारिता के माध्यम से साकार किया जा रहा है। सहकारिता एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तिम छोर तक जुड़ा हुआ है।

Now a days financial literacy compaign is going on by NABARD. Financial literacy is more essential in rural areas instead of urban areas. Due to lack of financial awareness in literate and illiterate people of rural areas, the need of financial education is must. This important work is doing well by NABARD with the help of cooperative. The cooperative is the robust medium that is directly connected to tail of rural areas.

मुख्य शब्द : सहकारिता, वित्तीय साक्षरता, नाबार्ड (NABARD) सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय समन्वयक, सहकारी बैंक, चैक एवं विड्राल, टैक्स रिटर्न। Cooperative, Financial Literacy, NABARD (National Bank of Agriculture and Rural Development), Information Technology, Financial Coordinator, Cooperative Bank, Cheque & Withdrawl, Tax Return

प्रस्तावना

वित्तीय साक्षरता का तात्पर्य है – “धन के समुचित तरीके से उपयोग को समझना”। दूसरे शब्दों में धन के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना। जिससे हम अपने धन का सही प्रबन्धन करते हुये अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित एवं बेहतर बना सकें।

वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता इसलिये है क्योंकि वर्तमान समय में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के उत्तरोत्तर विकास एवं बढ़ते प्रवलन के कारण बिना इसके गति संभव नहीं है।

वित्तीय शिक्षा से मनुष्य के विचारों में बदलाव आता है जिससे उसकी कार्यशैली परिवर्तित होती है। फलस्वरूप उसके परिणाम भी बेहतर आते हैं। इस तरह जब वित्तीय विचारों में बदलाव आयेगा तो समाज में भी बदलाव परिलक्षित होगा। जब समाज वित्तीय साक्षर होगा तो हमारा देश भी वित्तीय रूप से मजबूत हो जायेगा। इससे हमारे देश का आर्थिक स्वरूप ही बदल जायेगा।

वित्तीय शिक्षा का प्रसार करना हमारा फर्ज और कर्तव्य दोनों है। इस महत्वपूर्ण कार्य को नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों में एक वित्तीय समन्वयक नियुक्त कर आवश्यक तकनीकी संसाधन उपलब्ध करवाये गये हैं। समन्वयक द्वारा बैंक में आने वाले नियक्षर व अनभिज्ञ ग्रामीणों को वित्तीय शिक्षा के बारे में बताया जाता है। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक और पाक्षिक रूप से भिन्न-भिन्न गांवों में कैम्प आयोजित कर ग्रामीणों को वित्तीय साक्षर किया जाता है। उन्हे वित संबंधी, बैंकिंग लेनदेन संबंधी, चैक और विड्राल संबंधी, एटीएम संबंधी जानकारी एवं सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत करवाया जाता है। वित्तीय साक्षर होने पर ग्रामीणों द्वारा योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाया जाता है। इससे ग्रामीणों का आर्थिक व सामाजिक विकास होता है।

अध्ययन क्षेत्र

हनुमानगढ़ जिले की स्थापना 12 जुलाई 1994 को जिला श्री गंगानगर से अलग कर की गयी। यह घग्गर नदी के दोनों ओर स्थित है। इसका पुराना नाम सादुलगढ़ है। यह एक कृषि प्रधान जिला है। यह जिला पंजाब व हरियाणा दोनों राज्यों की सीमाओं से सटा हुआ है। इस कारण यहाँ मिली जुली संस्कृति देखने को मिलती है।

हनुमानगढ़ जिले में 2 लोकसभा क्षेत्र (गंगानगर व चुरु), पांच विधानसभा क्षेत्र (संगरिया, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, नोहर तथा भादरा) तथा सात उपखण्ड, सात तहसील व सात पंचायत समिति है। जिले में सहकारिता के क्षेत्र में हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक, ग्राम सेवा सहकारी समितियां, श्रीगंगानगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिंग, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, हनुमानगढ़ सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार आदि संस्थाएं संचालित हैं। यहाँ की मुख्य फसले रबी (चना, सरसों, गेहूँ, अरण्ड, तारामीरा) तथा खरीफ (नरमा, कपास, धान, ग्वार, मूंग, मोठ, ज्वार व बाजरा) हैं।

समस्या अधिकरण

वित्तीय साक्षरता ग्रामीण एवं पिछड़े वर्ग के लिये वरदान साबित होगी क्योंकि धन का प्रबन्धन एवं उसके लेनदेन के बारे में ज्ञान होना आर्थिक विकास की ओर अग्रसर करता है। वित्तीय साक्षर होने से ग्रामीण लोग धोखेबाज व जालसाज लोगों के चंगुल में फंसने से बच जायेंगे। इसलिये वर्तमान समय में वित्तीय निरक्षरता एक नयी समस्या के रूप में ऊभर कर सामने आयी है। जिसका निराकरण वित्तीय साक्षरता से ही सम्भव है।

शोध विधि

शोध प्रक्रिया के अन्तर्गत अनुसंधान विधियों का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। अनुसंधान विधियां समस्या के समरूपण, पदों की परिभाषा, अध्ययन के लिये विषयों के विकल्प, आंकड़ों के संग्रहण, उनकी वैधता और अनुमानों की प्रक्रियाओं के सन्दर्भ में सूचनाएं प्रदान करती हैं। इस शोध को पूरा करने के लिये सर्वेक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, सहभागी अवलोकन, व्यौक्तिक अध्ययन, साक्षात्कार अनुसूचि आदि विधियों का प्रयोग किया जा सकता है।

सर्वेक्षण विधि

इस विधि की सहायता से किसी भी पक्ष, विषय या समस्या का खोजपूर्ण निरीक्षण किया जाता है तथा उससे संबंधित विश्वसनीय तथ्यों का संकलन कर वास्तविक निष्कर्ष निकाले जाते हैं।

साक्षात्कार अनुसूची

इस अनुसूची में सूचनाएं प्रश्नों के रूप में होती है जिसे प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा पूछकर भरा जाता है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. इस अध्ययन का उद्देश्य है कि वास्तव में वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता है या नहीं।
2. इस अध्ययन का उद्देश्य है कि ग्रामीणों को वित्तीय साक्षरता के माध्यम से लाभ हुआ या नहीं।
3. इस अध्ययन का उद्देश्य है कि कृषकों को बैंकिंग सुविधाएं सुलभ हुयी या नहीं।

4. इस अध्ययन का उद्देश्य है कि नाबाड़ द्वारा संचालित वित्तीय साक्षरता अभियान कारगर साबित हुआ या नहीं।
5. इस अध्ययन का उद्देश्य है कि वित्तीय साक्षरता से ग्रामीणों एवं पिछड़े वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला या नहीं।
6. इस अध्ययन का उद्देश्य है कि वित्तीय निरक्षर होने के कारण ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान हुआ या नहीं।

प्राकृत्यना

1. ग्रामीणों को आर्थिक रूप से उन्नत करने में वित्तीय साक्षरता का कितना योगदान रहा?
2. वित्तीय साक्षरता द्वारा सभी कृषकों को वित्तीय जानकारी उपलब्ध हुयी या नहीं।
3. वित्तीय साक्षरता में सहकारिता का कितना योगदान रहा?
4. ग्रामीण वित्तीय लेनदेन के मामले में आत्मनिर्भर हुये या नहीं।
5. ग्रामीणों को वित्तीय योजनाओं की जानकारी एवं लाभ प्राप्त हुआ या नहीं।
6. वित्तीय साक्षरता का सफल संचालन हो रहा है या नहीं।

निष्कर्ष

इस प्रकार अन्त में यह कहा जा सकता है कि वित्तीय साक्षरता ने ग्रामीण परिवेश को एक सुदृढ़ आधार प्रदान कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वित्तीय साक्षरता से ग्रामीणों को अब वित्तीय योजनाओं का ज्ञान, रिटर्न की समझ, सही उत्पाद का चयन, रियल टैक्स रिटर्न, उत्पाद प्रदाता कम्पनी का चयन आदि सभी की समझ आने लगी है तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण स्वयं को ठगा हुआ महसूस नहीं करता है।

भारत एक कृषि प्रधान व गांवों का देश है अतः यहाँ की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि से अपना जीवन यापन करती है। वित्तीय साक्षरता ने इन कृषकों की समस्याओं को समझ कर उन्हें वित्तीय लेनदेन के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है। वर्तमान में यह आवश्यक है कि वित्तीय साक्षरता संबंधी शिक्षा को विद्यालय अथवा महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में एक आवश्यक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाये।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Abdul Aziz N.P. and S.M. Jawed Akhtar – “Financial Literacy and Inclusion in India” – New Century Publications.
2. Shaun M Durrant “Financial Literacy” Pages -172
3. K.G. Karmakar, G.D. Banerjee, N.P. Mahapatra- 2011 “Towards Financial Inclusion in India” – Sage Publications Pvt. Ltd.
4. Jyotinath Ganguly “The Legacy of Financial Literacy” – Notion Press Media Pvt. Ltd. – Pages -114.
5. S.C. Dube, “India’s Changing Village”
6. कपिल, एच०के० 1981, “अनुसंधान विधियाँ”, हरिप्रसाद भार्गव, पुस्तक प्रकाशन, आगरा